

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1395
जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13 अप्रृहायण, 1946 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना

1395. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो लाभार्थियों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या पहल की गई है;
- (घ) क्या एआई और ब्लॉकचैन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) भिवानी-महेंद्रगढ़ में आईटी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

- (क) से
- (ङ): ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रतिपरिवार एकव्यक्ति) तक पहुंचना था। यह योजना समाप्त हो चुकी है। इसके तहत 31 मार्च, 2024 तक तय की गए लक्ष्य 6 करोड़ की तुलना में देशभर में 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्धि अनुबंध में दी गई है।

एमईआईटीवाई भारत सरकार ने प्रतिसीट ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता देकर छोटे शहरों में रोजगार सृजन और आईटी/आईटीईएस को बढ़ावा देने के लिए भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) शुरू की है। इन योजनाओं में स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में संचालित देशभर में बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों के माध्यम से महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

भारत दुनिया की आईटी कौशल राजधानी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 42 संकेतकों के आधार पर वैश्विक और राष्ट्रीय एआईवाइब्रेसीरैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के साथ भारत को शीर्ष 4 में स्थान दिया है।

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक दम उठार ही है कि हम आईटी कौशल में अपनी बढ़त बना एवं खेलें। एमईआईटीवाई ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के साथ संयुक्त रूप से "प्यूर्चरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नई/उभरती प्रौद्योगिकियों अर्थात् ब्लॉकचैन, कॉर्ट्रिम बैड्रिमता, रोबोटिक प्रोसेस और ऑटोमेशन, ऑगमेटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिंगडेटा एनालिटिक्स, एडिटिव मैच्यूफैक्चरिंग/3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल और साइबर सुरक्षा में उम्मीदवारों का पुनः कौशलन/कौशल उन्नयन करना है।

इसके अलावा, इंडिया एआईमिशन के इंडिया एआई प्यूर्चरस्किल्स के तहत, सभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों के बी.टेक और एम.टेक छात्रों को इंडिया एआई फेलोशिप प्रदान की जाती है।

हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ जिलों सहित पूरे देशभर में पीएमजीदिशा योजना के तहत आईटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे। विवरण नीचे दिया गया है:

ज़िला	प्रशिक्षण केंद्र	पंजीकृत उम्मीदवार	प्रशिक्षित उम्मीदवार
भिवानी	858	86,167	72,171

अनुबंध

पीएमजीदिशायोजनाकेअंतर्गतराज्य/संघराज्यक्षेत्रवारउपलब्धियां

क्रमसं.	राज्यकानाम	पंजीकृतउम्मीदवार	प्रशिक्षितउम्मीदवार
1	अंडमान व निकोबारद्वीपसमूह	5,564	2,931
2	आंध्रप्रदेश	23,01,731	19,17,452
3	अरुणाचलप्रदेश	14,949	11,615
4	असम	27,21,585	23,60,195
5	बिहार	82,40,606	74,12,740
6	छत्तीसगढ़	24,86,455	21,37,064
7	दादरऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदीव	20,522	18,029
8	गोवा	58,569	53,784
9	गुजरात	30,31,310	26,83,286
10	हरियाणा	18,57,815	15,77,109
11	हिमाचलप्रदेश	6,61,922	5,32,976
12	जम्मूऔरकश्मीर	8,70,451	7,06,991
13	झारखंड	27,52,731	22,86,356
14	कर्नाटक	29,64,726	24,40,957
15	केरल	1,77,165	1,18,132
16	लद्दाख	24,785	22,122
17	लक्ष्द्वीप	142	35
18	मध्यप्रदेश	56,92,467	50,69,449
19	महाराष्ट्र	61,23,970	53,23,817
20	मणिपुर	28,397	18,286
21	मेघालय	1,52,783	1,06,063
22	मिजोरम	30,317	23,125
23	नागालैंड	11,990	8,968
24	ओडिशा	36,16,441	30,86,143
25	पुडुचेरी	22,079	15,801
26	पंजाब	17,46,448	15,14,820
27	राजस्थान	45,06,184	39,70,690
28	सिक्किम	27,035	23,122
29	तमिलनाडु	17,04,537	14,07,880
30	तेलंगाना	14,56,226	12,10,448
31	त्रिपुरा	3,25,000	2,64,186
32	उत्तर प्रदेश	1,63,14,369	1,45,48,273
33	उत्तराखण्ड	7,85,978	6,73,306
34	पश्चिमबंगाल	28,36,714	23,95,565
कुल		7,35,71,963	6,39,41,716

*चंडीगढ़औरदिल्लीशहरीक्षेत्रमेहैं, इसलिएइसयोजनाकेअंतर्गतशामिलनहींकिए गएहैं।
